कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंज़ूरी दी

सिविल सेवा परीक्षा में इस विषय का महत्व:
GS -2: कृषि नीति और योजना
GS – 3 : कृषि विकास

संदर्भ:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज छह वर्ष की अवधि के लिए "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" को स्वीकृति दे दी।

योजना के महत्वपूर्ण पहलू:

- यह योजना 2025-26 से 100 ज़िलों में लागू होगी।
- नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है।

उद्देश्य:

- योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है।
- यह 2025-26 के केंद्रीय बजट में "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" के अंतर्गत 100 ज़िले विकसित किये जाने की घोषणा के अनुरूप है।

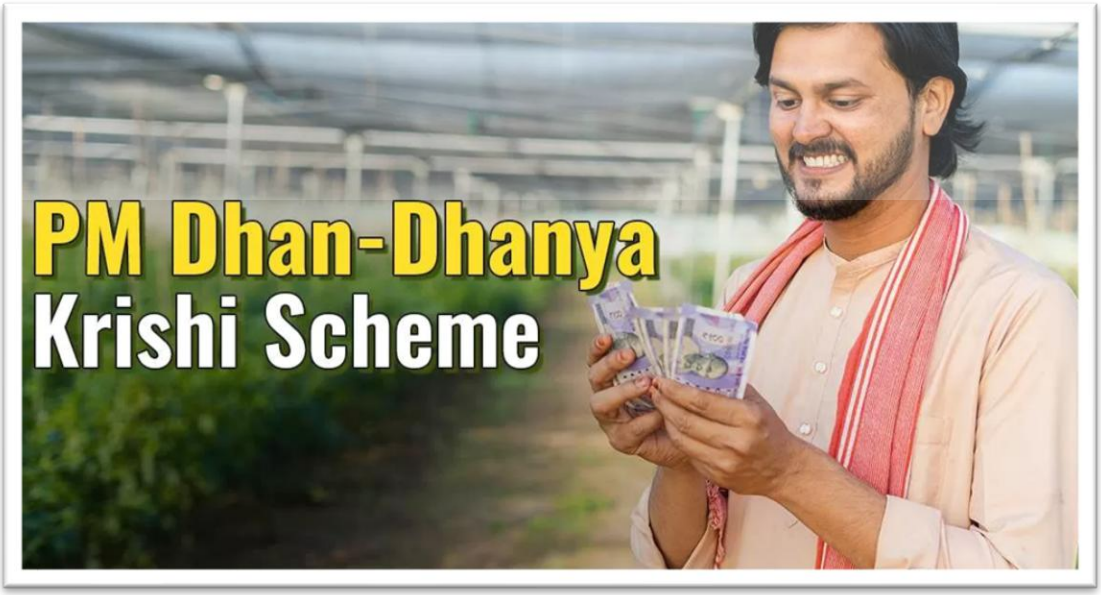

Result Mitra

इसका क्रियान्वयन:

योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा।

चयन के आधार:

• तीन प्रमुख संकेतकों- कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर सौ जिले चिन्हित किये जाएंगे।

• प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र (वह कुल क्षेत्रफल, जहां किसी कृषि वर्ष में वास्तव में फसलें उगाई जाती हैं) और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी।

• इस योजना में प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा।

निगरानी:

• योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी।

• जिला धन धान्य समिति द्वारा जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

• समिति में प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे।

• प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना में प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों के अनुसार की जाएगी।

• नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा।

• इसके अलावा, प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।

परिणाम:

• योजना के परिणामस्वरूप उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी।

• कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन (उत्पाद और सेवा में उन्नयन) होगा।

• स्थानीय आजीविका सृजित होगी।

• इस प्रकार इस योजना से घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल होगी।

• इन सौ जिलों के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार के साथ ही राष्ट्रीय संकेतकों में भी स्वतः ही वृद्धि होगी।

Result Mitra

PYQ

प्रश्न 1: भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपज के मूल्यवर्धन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें।

UPSC Mains 2020

प्रश्न 2: कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को किस प्रकार की व्यवस्थाएँ और निगरानी तंत्र बनाने चाहिए?

UPSC Mains 2018

प्रश्न 3. प्रश्न: भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

UPSC Mains 2017

Result Mitra